



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

C. K. K. K.
11-85

सं० 535] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 5, 1984/कार्तिक 14, 1906
No. 535] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5, 1984/KARTICKA 14, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1984

का. आ. 820(अ) :—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तारीख 19 मार्च, 1984 की अधिसूचना सं. का. आ. 169 (अ) और तारीख 1 मई, 1984 की अधिसूचना सं. का. आ. 338(अ) और अधिसूचना सं. का. आ. 339(अ) में अन्तर्विष्ट विषय पर न्यायनिर्णयन करने के लिए "विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (नियारण) अधिकरण" का भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 308(अ) तारीख 16 अप्रैल, 1984 द्वारा गठन किया गया था, जिसमें न्यायमूर्ति श्री पुलियनगुडी रमैया पिल्लै गोकुलाकृष्णन, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, और अधिकरण ने अपना कार्य पूरा कर लिया है ;

और यह कि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिकरण का बना रहना आवश्यक नहीं है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती हैं कि उपर्युक्त अधिकरण राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अस्तित्व में नहीं रहेंगे ।

[सं. 11/17017/54/84-आई.एस. (यू.एस.-डी-2)]

एल. एन. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 1984

S.O. 820(E).—Whereas the “Unlawful Activities (Prevention) Tribunal” consisting of Shri Justice Puliangudi Ramaiya Pillai Gokulakrishnan, Judge of Madras High Court, constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 308(E) dated the 10th April, 1984, to adjudicate upon the matter contained in the notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 169(E) dated 19th March, 1984 and S.O. 336(E) and S.O. 359(E) dated the 1st May, 1984, has completed its work;

And whereas the Central Government is of opinion that the continued existence of the said Tribunal is unnecessary;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (i) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby directs that the aforesaid Tribunal shall cease to exist with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. II/17017/54/84-IS(US-D.II)]

L. N. GUPTA, Jt. Secy.